अध्याय- 4

4

लोकतंत्र की उपलब्धियाँ

परिचय

कक्षा 9 में हमने लोकतंत्र की बुनियादी बातों, इसकी संस्थाओं और इसके नियमों-कायदों का विस्तार से अध्ययन किया है । साथ ही, इस पुस्तक के पिछले अध्यायों से हमने लोकतंत्र की बारीकियों पर गौर भी किया है । लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हमने राजनीति को काफी करीब से देखा है। स्वाभाविक है कि सत्ता में साझेदारी को समझने के क्रम में विचार एवं आदर्श, सहयोग व समन्वय और संघर्ष व प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दे कुछ जरूरी सवालों को जानने की उत्कंठा पैदा करते हैं । उदाहरण के तौर पर यदि सिद्धांत रूप में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, तो वह क्यों नहीं व्यवहार में सामाजिक समस्या, समानता और व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता की कसौटी पर खरा उतरता ? ऐसा इसलिए कि लोकतंत्र अपनी गुणवत्ता के कारण हमारे भीतर उम्मीदें पैदा करता है । अत: ये सवाल स्वाभाविक एवं सकारात्मक है । लोकतंत्र की उपलब्धियों को जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये सवाल हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे । इस क्रम में हमारी शंकाओं का समाधान होगा और साथ ही स्वस्थ लोकतंत्र का विकास भी होगा । इस अध्याय में लोकतंत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन कई स्तरों पर किया जायेगा, ताकि साझी समझ के साथ लोकतंत्र पर बातचीत करने का क्रम निरंतर जारी रह सके । इस क्रम में हम भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे।

क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है ?

आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है । लोकतंत्र का लगातार प्रसार एवं उसे मिलनेवाला जनसमर्थन यह साबित करता है कि लोकतंत्र

अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है । इन व्यवस्था में सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा आकर्षण के बिन्दु हैं । साथ ही, इसमें आपसी विभेदों एवं टकरावों को कम करने और गुण–दोष के आधार पर सुधार की निरंतर संभावनाएँ लोगों को इसके करीब लाती हैं । इस प्रसंग में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति–विशेष द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक सहमति के आधार के लिये जाते हैं । यह विशेषता लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी है ।

लोकतंत्र के प्रति लोगों की उम्मीदों के साथ–साथ शिकायतें भी कम नहीं होती है । लोकतंत्र से लोगों की अपेक्षाएँ इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसकी थोड़ी सी भी कमी खलने लगती है। कभी–कभी तो हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेने का भी खतरा मोल लेते हैं और इसे तमाम सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विषमता को समाप्त करनेवाली जादुई व्यवस्था मान लेते हैं । इस तरह का अतिवादी दृष्टिकोण लोगों में इसके प्रति अरूचि एवं उपेक्षा भी पैदा करता है। परन्तु, लोकतंत्र के प्रति यह नजरिया न तो सिद्धांत रूप में और न ही व्यावहारिक धरातल पर स्वीकार्य है । अतएव, लोकतंत्र की उपलब्धियां को जांचने–परखने के पहले हमें यह समझ बनानी पड़ेगी कि लोकतंत्र अन्य शासन–व्यवस्थाओं से बेहतर एवं जनोन्मुखी है तथा यह चीजों को हासिल करने की स्थितियों का निर्माण कर सकता है । अब नागरिकों का दायित्व है कि वे इन स्थितियों से लाभ उठाकर लक्ष्य की प्राप्त करें।

इसी संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों को भी परखा जाना चाहिए । यह सच्चाई है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के काले पक्षों को दर्शाने वाले उदाहरणों की कमी नहीं है। आजादी के पश्चात् विगत 60 वर्षों के इतिहास में भ्रष्टाचार में डूबे राजनीतिज्ञ और लोकतांत्रिक संविधान के मूल उद्देश्यों को विनष्ट करने वालों किस्मों की कमी नहीं है । इन तमाम कमजोरियों के बावजूद हमारा लोकतंत्र पश्चिम के लोकतंत्र से नायाब है जो निरंतर विकास एवं परिवर्द्धन की ओर उन्मुख है ।

तात्पर्य यह कि हमें लोकतंत्र को एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में देखते हुए इसकी उपलब्धियों को मूल्यांकित करना चाहिए । तो आइए, हम लोकतंत्र से अपेक्षित कतिपय मौलिक तत्त्वों को परखने का प्रयास करें और इसकी तुलना गैर–लोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हुए सकारात्मक समझ बनाने की कोशिश करें ।

उत्तरदायी एवं वैध शासन

लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस हद तक वैध है, इसे जांचने के लिए जरूरी है कि हम सवाल करें कि –

(क) क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है ?

(ख) क्या चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है ?

(ग) क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिये जाते हैं और फैसले कितने जनकल्याणकारी होते हैं?

उपर्युक्त सवालों के आइने में लोकतंत्र का यदि मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि लोग चुनावों में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करते हैं । यह और बात है कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत लोगों का दबदबा इसमें देखा जाता है । इसके बावजूद भी जनता में जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार इसमें सुधार की संभावनाएँ बनी रहती हैं । उल्लेखनीय है कि शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के कारण आज लोग अपने मताधिकार का बढ़–चढ़कर उपयोग कर रहे हैं, जबकि पूर्व में उन्हें या तो वंचित किया जाता था अथवा उनकी रुचि नहीं रहती थी । इस बात को यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो स्थितियाँ संतोषप्रद है । अभिवंचित वर्ग के लोगों को कभी समाज के श्रेष्ठजनों द्वारा मताधिकार से वंचित किया जाता था, वे आज मुखर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने अधिकारों की बातें करते हैं । ध्यान से देखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र के ढाँचागत स्वरूप में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है; फिर भी लोगों का लोकतंत्र के प्रति आस्था के चलते स्थितियाँ बदली हैं। आज लोग सिर्फ मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार की निर्णय–प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं । यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि उसे जनता द्वारा नकारने का खतरा बरकरार रहता है ।

अब हम दूसरे सवाल के परिपेक्ष्य में सोंचे । यह सच्चाई है कि लोकतंत्र में बहस–मुवाहिसों के बाद ही फैसले किए जाते हैं । फैसलों को विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता

है । स्वाभाविक कि फैसलों में अनिवार्य रूप से विलंब होता है । कभी-कभी तो अत्यधिक विलंब के कारण लिए गए फैसले भी अप्रासंगिक हो जाते हैं । वहीं दूसरी ओर फैसलों में विलंब के मामले को यदि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था से करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ फैसले शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं । यहाँ गौर करने की बात यह है कि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले किसी खास व्यक्ति द्वारा बगैर बहन-मुबाहिसों के लिए जाते हैं । इन फैसलों को लंबी विधायी प्रक्रिया से भी गुजरना नहीं पड़ता है । शीघ्रता से लिए ये फैसले कभी-कभी प्रासंगिक एवं न्यायोचित भी लगते हैं । लोग राहत का भी अहसास करते हैं । परन्तु इसके फैसलों को यदि हम समग्रता से देखते हैं तो काफी क्षोभ एवं निराशा होती है । कारण स्पष्ट है कि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है जो कभी सामूहिक जनकल्याण की दृष्टि से दुरूस्त नहीं होती है । परन्तु, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को यह जानने का हक होता है कि फैसले कैसे एवं किस प्रकार से लिए जाते हैं । तात्पर्य यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं संतोष का भाव प्रलक्षित होता है जबकि गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं रहती है । निष्कर्षत: हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होते हैं । सरकार जब कानून बनाती है तो उसपर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जनता के बीच भी खुलकर चर्चाएँ होती हैं ।

इस प्रकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है । गैरलोकतांत्रिक व्यवस्था से तुलना के पश्चात् कोई संदेह नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है । यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और सभी देश अपने को लोकतांत्रिक कहने में गर्व का अनुभव करते हैं ।

आर्थिक समृद्धि और विकास

अभी तक की जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है । इस आधार पर यह सोचना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस व्यवस्था में सरकारें अच्छी होंगी । साथ ही, यहाँ आर्थिक खुशहाली होगी और विकास की दृष्टि

से भी अग्रणी होगा । लेकिन जब हम लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन–व्यवस्था में आर्थिक खुशहाली और विकास की दरों पर गौर करते हैं तो काफी निराशा होती है । नीचे अंकित चार्ट के अवलोकन से एक प्रश्न और भी उठता है कि आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से क्या लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था से बहतर है ? चार्ट को गौर से देखें ।

विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें (1950-2000)

शासन का प्रकार और देश	विकास दर
सभी लोकतांत्रिक शासन	3.95
सभी तानाशाहियाँ	4.42
तानाशाही वाले गरीब देश	4.34
लोकतंत्र वाले गरीब देश	4.28

उपर्युक्त आँकड़ों के अवलोकन से लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था से निराशा तो होती है । परन्तु किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएँ, अन्य देशों से सहयोग के साथ–साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करती है । लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर में कमी के बावजूद, लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं जिसका एहसास हमें धीरे–धीरे होता है, जो अंतत: सुखद होता है ।

सामाजिक विषमता और सामंजस्य

समाज में विद्यमान अनेक सामाजिक विषमताओं, जिसे हम विविधताओं के रूप में भी देख सकते हैं, आपसी समझदारी एवं विश्वास को बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है । तात्पर्य यह कि लोकतंत्र नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायक होता है । हमने अध्याय दो में कई दृष्टांतों से इस बात को महसूस किया है कि लोकतंत्र विभिन्न जातियों एवं धर्मों के विभाजक

कारकों के बीच वैमनस्य एवं भ्रांतियों को कम करने में सहायक हुआ है । साथ ही लोकतंत्र उनके बीच टकरावों को हिंसक एवं विस्फोटक बनने से रोका है । अपने देश में भी जातीय टकरावों एवं सांप्रदायिक उन्मादों को व्यापक स्तर पर रोकने में लोकतंत्र सहायक हुआ है । कहना न होगा कि यदि लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था नहीं होती, तो निश्चित तौर पर स्थिति भयावह होगी।

यह सच है कि समाज में विभिन्न जातीय, भाषायी एवं सांप्रदायिक समूहों में मतभेदों एवं टकरावों को पूरी तरह से समाप्त कर देने का दावा कोई भी शासन-व्यवस्था नहीं कर सकती है। ऐसे मतभेदों के बने रहने के कई सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण हैं । इनके बीच टकराव तब होते हैं जब इनकी बातों की अनदेखी की जाती है अथवा इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है । अक्सर गैरलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसी प्रवृत्तियाँ देखी जाती है । हाल ही में नेपाल में जनता की आकांक्षाओं की अनदेखी की गई एवं राजपरिवार के इशारे पर दमन का चक्र चलाया गया । अंततः जनता की ही जीत हुई । सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों के बीच बातचीत एवं आपसी समझदारी के माहौल के निर्माण में लोकतंत्र की अहम् भूमिका होती है । लोकतंत्र लोगों के बीच एक-दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान भाव को विकसित करता है । इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक विषमताओं एवं विविधताओं के बीच संवाद एवं सामंजस्य के निर्माण में सिर्फ लोकतंत्र ही सफल रहा है । इस बात को हम इतिहास की पुस्तक में उल्लिखित जनसंघर्ष की कहानियों में देख सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त, नागरिकों की गरिमा एवं उनकी आजादी की दृष्टि से भी लोकतंत्र अन्य शासन-व्यवस्थाओं में सिर्फ आगे ही नहीं है बल्कि सर्वोत्तम है । लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाईश बनी रहती है। संवाद का अर्थ है वाद-विवाद के पश्चात एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश । अर्थात् अपनी बातों को निर्भीकता से रखना और दूसरों

> आपकी परीक्षा वर्ष में दो-तीन बार होती है परंतु, लोकतंत्र की हर रोज परीक्षा होती है जिसे देश की जनता लेती है ।

की बातों को गंभीरता से सुनने की स्वस्थ परंपरा निर्मित करना। इस दृष्टि से लोकतंत्र से बेहतर और कोई दूसरी शासन–व्यवस्था नहीं हो सकती है, जहाँ हर तरह की आजादी होती है ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक विषमताओं एवं विविधताओं के बीच आपसी समझदारी एवं सामंजस्य के निर्माण मे लोकतंत्र अन्य गैरलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना में काफी आगे है, जहाँ बातचीत की निरंतर की संभावनाएँ बनी रहती हैं ।

भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है ?

इनकी तमाम उपलब्धियों एवं परिणामों के परिपेक्ष्य में जब हम भारतीय लोकतंत्र का अवलोकन करते हैं तो हमारे मन में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ होती हैं । निराशा भी होती है, लेकिन आशाएँ भी जगती है । हमारी निराशाएँ पहले इस रूप में प्रकट होती हैं कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं अथवा भारत लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है । कभी–कभी तो ऐसी टिपणियाँ भी सुनने को मिलती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तमाम शासन–व्यवस्थाओं की तुलना में असफल एवं पंगु है । स्वाभाविक है कि लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है । अतएव इसकी गति निश्चित तौर पर धीमी होती है । न्याय में विलंब, विकास दर की धीमी रफ्तार के कारण ऐसा लगने लगता है कि लोकतंत्र बेहतर नहीं है । राजतंत्र एवं तानाशाही व्यवस्था में इसकी गति तेज तो होती है परंतु उसमें व्यापक जन कल्याण के तत्त्व एक सिरे से गायब रहते हैं । साथ ही, गुणवत्ता का सर्वथा अभाव दिखता है ।

इन निराशाओं के बावजूद आशा की किरण फिर भी प्रस्फुटित होती है । गैरलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आनन–फानन में शीघ्रता से लिये गये निर्णयों के दुष्परिणामों से जब हम मुखातिब होते हैं, तब लगता है कि लोकतंत्र से बेहतर और कोई शासन–यवस्था हो नहीं सकती है। इसे जब हम भारतीय लोकतंत्र के 60 वर्षों की अवधि के संदर्भ में देखते हैं तो लगता है कि कालक्रम में हम काफी सफल रहे हैं । एक समय था जब लोग ''कोई नृप होउ हमें का हानि'' के मुहावरे में बाते करते थे । शासन–व्यवस्था में आम जनता अपने को भागीदार नहीं मानती थी । जनता जज्बातों एवं भावनाओं में अपना वोट करती थी । धनाढ्य एवं आपराधिक छवि के उम्मीदवार

जनता के मतों को खरीदने का जज्बा रहते थे । परन्तु, जब हम 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनावों का मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि भारत की जनता ने एक साथ पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को समूल खारिज कर दिया है । जनता को अब विश्वास हो गया है कि वह अपने मतों से किसी को गिरा एवं उठा सकती है । आज पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की साख बढ़ी है और इसकी सफलता से अन्य लोकतांत्रिक देश अनुप्राणित हो रहे हैं। यह सच है लोकतंत्र को बार-बार जनता की परीक्षाओं में खरा उतरना पड़ता है । लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो उनकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती है । वे लोकतंत्र से और अच्छे कामों की उम्मीद करने लगते हैं । अतएव आप जब कभी किसी से लोकतंत्र के कामकाज एवं भविष्य पर प्रश्न पूछेंगे, तो वे अपनी निजी अथवा सार्वजनिक समस्याओं को पिटारा खोल देंगे । लोकतंत्र से जनता की अपेक्षाएँ एवं शिकायतें इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र कितना गतिमान एवं सफल है । जनता का संतुष्ट होना दो बातों का द्योतक है । पहला कि तानाशाही व्यवस्था में जनता जबरन संतुष्ट है और दूसरा कि जनता का लोकतंत्र में रूचि नहीं है । तात्पर्य यह कि किसी तानाशह के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं कर पाती है जबकि लोंकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का मूल्यांकन जनता हर रोज करती है । इस परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे, तो स्थितियाँ संतोषजनक प्रतीत होंगी । आज भारतवर्ष में जनता का लगातार प्रजा से नागरिक बनने की प्रक्रिया जारी है।

भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारण तत्त्व

नि:संदेह, भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है । उत्तरोत्तर इसके विकास से जनता की भागीदारी में विस्तार हुआ है । फिर भी भारतीय लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है । कारण कि जनता का जुड़ाव उस स्तर तक नहीं पहुँचा है, जहाँ जनता सीधे-तौर पर हस्तक्षेप कर सके । अतएव इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो । शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती है । यह सच्चाई है लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती हैं, परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलनेवाली व्यवस्था नहीं है बल्कि

विश्वास और आंतरिक लोकतंत्र

यहाँ अल्पमत की आकांक्षाओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है । भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह अवसर अवश्य प्रदान करें ताकि वे किसी–न–किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके । लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ–साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो । अर्थात् सार्वजनिक मुद्दों पर बहस–मुबाहिसों में कमी नहीं हो । राजनीतिक दलों के लिए तो यह अतिआवश्यक है क्योंकि सत्ता की बागडोर संभालना उनका लक्ष्य होता है । विडम्बना है कि भारतवर्ष में नागरिकों के स्तर पर और खासतौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का सर्वथा अभाव दिखता है । जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र एवं व्यवहार गैरलोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी । इसे हम अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर सकते हैं ।

प्रश्नावली

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long-Answer Questions)

1. लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है ?
2. लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक संवृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है ?
3. लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है ?
4. लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है ?
   (क) राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है
   (ख) लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है
   (ग) बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एस–सा व्यवहार करता है
   (घ) समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का कम कर दिया है ।

5. इनमें से कौन-सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है ?

(क) कानून के समक्ष समानता (ख) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

(ग) उत्तरदायी शासन-व्यवस्था (घ) बहुसंख्यकों का शासन

6. लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन-सा सर्वेक्षण सही और कौन गलत प्रतीत होता (लिखें सत्य/असत्य)

(i) लोकतंत्र और विकास साथ-साथ चलते हैं ।

(ii) लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएँ बनीं रहती है ?

(iii) तानाशाही में असमानताएँ नहीं होती ।

(iv) तानाशाही व्यवस्थाएँ लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है ।

7. भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन-सा कथन सही अथवा गलत है-

(i) आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे हैं

(ii) शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन बेहतर नहीं है

(iii) अभिवंचित वर्ग के लोग चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं ?

(iv) राजनीतिक दृष्टि से महिलाएँ पहले अधिक सत्ता में भागीदार बन रही है ।

8. भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं ?

9. भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है ?

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

*